मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों का भ्रमण करवा रही है। योजना के अंतर्गत आज उन्होंने बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

डॉ. अंबेडकर ने भेद-भाव रहित समाज का मार्ग दिखाया- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंबेडकर जयन्ती समारोह में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया

- **उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने सभी वर्गों में शिक्षा पर जोर दिया और महिला सशक्तिकरण व श्रम सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।**

जयपुर, 14 अप्रेल। सोमवार को राजस्थान इन्टरनैशनल सैंटर में आयोजित डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए भेद-भाव रहित समाज का मार्ग दिखाया है।

शर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने सभी वर्गों में शिक्षा पर जोर दिया और महिला सशक्तिकरण तथा श्रम सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया उनके सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के माध्यम से आधारभूत संरचना एवं विकास के कार्य सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुडे पांच महत्वपूर्ण स्थानों, जन्म भूमि (महू), दीक्षा भूमि (नागपुर), महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली), चैत्य भूमि (मुंबई) और शिक्षा भूमि (लंदन) को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथ ही, उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के आदर्शों को जाने-समझें और प्रेरणा लें, इसी क्रम में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के तहत, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छकारों को सेफ्टी किट वितरित किए, साथ ही अजा/जजा के उद्यिमयों को औद्योगिक भूखंडों के पट्टे बांटे। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों का भ्रमण करवा रही है। योजना के अंतर्गत आज उन्होंने बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

समारोह में शर्मा ने बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को माथे से लगाकर नमन किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही, उन्होंने कुलदीप पंवार पाली को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार और डॉ अनुपमा सोनी को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किए।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वंचितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने जो भी वादे किए थे, वो पूरे किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र नायक, जयपुर सासंद मंजू शर्मा, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, विधायक गोरधन लाल, राम सहाय वर्मा, लालाराम बैरवा सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, संबंधित अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

मूल व डमी अभ्यर्थियों की फोटो मिक्सिंग करने वाला गिरफ्तार

अति महानिदेशक वी.के. सिंह ने कहा, उपनिरीक्षक पेपर लीक प्रकरण में 100 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं

- **फोटो मिक्सिंग करने वाले महेन्द्र कुमार ने रामनिवास विश्नोई और हनुमानाराम के फोटो मिक्स कर रामनिवास की फोटो बनाई, तथा नरपत लाल एवं हनुमानाराम की फोटो मिक्स कर नरपत लाल की फोटो बनाई।**

जयपुर, 14 अप्रेल। स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए मूल अभ्यर्थियों एवं डमी अभ्यर्थियों की फोटो मिक्सिंग कर फोटो बदलने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी प्रमुख वीके सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए मूल अभ्यर्थियों एवं डमी अभ्यर्थियों की फोटो मिक्सिंग कर फोटो की कूटरचना करने वाले आरोपी महेन्द्र कुमार (42), निवासी भीनमाल, जिला जालोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए 16 अप्रैल तक पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर सौंपा है। एसओजी द्वारा इस प्रकरण में अब तक 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र कुमार का भीनमाल में अजंता फोटो स्टूडियो है, जहाँ समारोह में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के काम के साथ- साथ फोटो मिक्सिंग का काम भी होता है। उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के लिए महेन्द्र कुमार ने रामनिवास विश्नोई एवं हनुमानाराम दोनों की फोटो को मिक्स कर रामनिवास की नई फोटो बनाई थी एवं नरपतलाल एवं हनुमानाराम दोनों की फोटो को मिक्स कर नरपतलाल की नई फोटो बनाई थी। इस मिक्स की हुई फोटो को हनुमानाराम ने 14 सितम्बर 2021 को नरपतलाल के एडमिट कार्ड पर चिपका कर उसके स्थान पर डमी बैठकर लिखित परीक्षा दी तथा 15 सितम्बर 2021 को रामनिवास के एडमिट कार्ड पर चिपका कर उसके स्थान पर डमी बैठकर लिखित परीक्षा दी एवं दोनों को लिखित परीक्षा में उतीर्ण करवाया। आरोपी महेन्द्र कुमार ने अन्य कितने अभ्यर्थियों की फोटो की मिक्सिंग की है, इस सम्बन्ध में एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

राम मंदिर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राम मंदिर का निर्माण न केवल आध्यात्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण देशवासियों की आस्था और संकल्प का परिणाम है। यह भारत की सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर और सशक्त करेगा।

चंपत राय ने जानकारी दी कि मंदिर परिसर से अब निर्माण मशीनें हटाई जाएंगी। प्रथम तल पर राजा राम, परकोटे और सप्तऋषियों के मंदिरों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा का कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। मंदिर का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है, जिससे भक्तों में उत्साह है।

सीमांत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष भी है। कई माकपा नेताओं की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।

सोमवार को भावनगर, मिनाखान, और संदेश खाली में भारी हिंसा हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ तथा उनके वाहन जला दिए गए। पुलिस थानों पर भी हमला किया गया।

इसी बीच, पुलिस अधिकारियों व राज्य के मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की, पर किसी ने नहीं सुनी। मुस्लिम दंगाई हिंसा पर उतारु रहे। इन क्षेत्रों के हिंदू सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, कइयों ने स्कूल भवनों में शरण ली है। भारी हिंसा के बाद भी ममता बनर्जी ने सिवाय कुछेक अपीलों के कुछ नहीं किया, वे चुप बैठी हैं।

हाई कोर्ट के दखल पर सफाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पद पर कार्य ग्रहण करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

याचिका में अधिवक्ता विकास सोमानी और एसएल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से साल 2018 में निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती में याचिकाकर्ता ने अजमेर जिले में आवेदन किया था। उसने नियमानुसार 16 जुलाई को कार्यग्रहण भी कर लिया था, लेकिन अगले दिन वह आकस्मिक कारण के चलते ड्यूटी से अनुपस्थित हुआ।

इस पर विभाग ने उसे सेवा से हटा दिया था। इसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर टोंक में आयोजित विचार-गोष्ठी को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने देश के सामाजिक ताने-बाने पर ऐसी छाप छोड़ी है कि आने वाली पीढ़ि यां सदियों तक बाबा साहेब को श्रृद्धापूर्वक याद करेगी।

अजीब सी शान्ति है, भारत के टॉप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव तथा अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ का धक्का भी बाज़ार गिरने के कारण बने।

इस उथल-पुथल के केन्द्र में हैं मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति में इस साल 3.42 अरब डॉलर की गिरावट आई है। अंबानी, जो कभी वैश्विक अमीरों की सूची में शीर्ष स्थान पर स्थिर थे, वे अब 17वें स्थान पर आ गए हैं, और उनकी अनुमानित संपत्ति 87.2 अरब डॉलर रह गई है। हालांकि, उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कुछ हद तक मजबूती दिखाई है, असली झटका जियो फायनैंशियल सर्विसेज़ से आया है, जिसमें 2025 में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इसके बाद हैं गौतम अडानी, भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में आक्रामक निवेश को लेकर लंबे समय से बाज़ार विश्लेषकों की राय बिल्कुल अलग-अलग है। अडानी की कुल संपत्ति में 6.05 अरब डॉलर की गिरावट आई है, क्योंकि अस्थिर स्टॉक मार्केट तथा समूह की उधारी को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में 9 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

लेकिन सबसे बड़ी चोट झेली है टैक्नोलॉजी अरबपति शिव नाडर ने। एच.सी.एल. के संस्थापक की संपत्ति में 10.5 अरब डॉलर की जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे वे इस साल, भारत के अरबपतियों में सबसे बड़े घाटे का सामना करने वाले बन गए हैं। वैश्विक आईटी खर्च में मंदी और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण, टैक क्षेत्र में आई सुस्ती ने नाडर की संपत्ति पर सीधा असर डाला है।

अन्य प्रमुख नामों में, जिंदल ग्रुप की प्रमुख सावित्री जिंदल, जिनकी संपत्ति में 2.4 अबर डॉलर की गिरावट आई है, जबकि सन फार्मा के दिलीप संघवी की संपत्ति 3.34 अरब डॉलर घटी है, क्योंकि रैगुलेटरी (नियामक) चुनौतियों और कमज़ोर कमाई ने फार्मा शेयरों को प्रभावित किया है।

दुख की बात ये है कि सिर्फ अरबपति ही नहीं, खुदरा निवेशक भी इस गिरावट की मार झेल रहे हैं। सैंसैक्स और निफ्टी में करीब 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडैक्स में क्रमश: 14 प्रतिशत और 17 प्रतिशत तक की तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (फॉरैन इन्स्टिट्यूशनल इन्वैस्टर) द्वारा लगातार अपना पैसा बाज़ार से निकालने से बाज़ार की गिरावट और तेज़ हो गई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए ताज़ा टैरिफ्स ने स्थिति को और उलझा दिया है, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ा है और निवेशकों की घबराहट भी।

भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए 2025 एक करारा सबक बनकर आया है। यह याद दिलाता है कि अरबों की नींव पर बने साम्राज्य भी वैश्विक बाज़ारों की बदलती हवाओं से अछूते नहीं रहते।

रामविलास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर रहेगा। वे करीब 30 वर्ष तक विधायक रहे हैं तथा लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली आरजेडी सरकार में एक बार मंत्री भी रहे थे।

राज्य सरकार ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर अदालत के ध्यान में लाया गया कि मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति देते समय संस्थानों में आवश्यक संकायों की संख्या, सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जाती है। इससे साफ पता चलता है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक संख्या में शिक्षण संकाय नहीं है तो वहां शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने खाली पदों को भरने की जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

इस पर अदालत ने दो सप्ताह में नियुक्तियों का रोडमैप पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के अधीन प्रदेश में चलने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज, निजी और स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर से चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं, जिसके चलते मेडिकल शिक्षा प्रभावित हो रही है।

संविधान के मूल ढांचे की रक्षा ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है-पायलट

राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने टोंक में अंबेडकर जयन्ती पर विचार गोष्ठी में भाग लिया

- **उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने शिक्षा पर ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, समाज, क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ सकता है।**

टोंक, 14 अप्रैल (निस) । बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष कर जो मुकाम हासिल किया, नाम-शौहरत कमायी, उसकी मिसाल दी जाती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर टोंक में आयोजित विचार-गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।

पायलट ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने देश के सामाजिक ताने-बाने पर ऐसी छाप छोड़ी है कि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक बाबा साहेब को श्रृद्धापूर्वक याद करेंगी।

उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, समाज, क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ सकती है। जो समाज, जो देश पूरी तरह से शिक्षित नहीं होता, वो पूरा विकसित नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि हमें बाबा साहेब को श्रृद्धांजलि देनी है, उनके सपनों को साकार करना है तो ज्यादा प्रासंगिक यह होगा कि उनके द्वारा निर्मित संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की जाये।

पायलट ने आज टोंक में आयोजित पार्टी के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा, बाबा साहेब ने कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो वे देश का संविधान नहीं बना पाते। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ चुनावों से भाजपा ने देश के इतिहास में एक ऐसा पहलू जोड़ दिया है जो हमारे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव करके उसे कमजोर करना ऐसे उदाहरण हैं, जो निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सजगता और सक्रियता से मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटवाने के कार्य सम्पन्न करवायें।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद बेग, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हंसराज गुंजल, सेवादल अध्यक्ष अब्दुल खालिक सहित, अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस आदेश के परिणामस्वरूप, यह मीटिंग राज्य सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम कदम है।

मुख्यमंत्री स्टालिन देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गये हैं, जिन्होंने राज्यपाल के अनिवार्य हस्ताक्षरों के बिना 10 विधेयक अधिनियमों के रूप में अधिसूचित कर दिये हैं। यह सब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सुफल है।

बुधवार की मीटिंग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सीधा और प्रत्यक्ष नतीजा है। हालाँकि स्टालिन सरकारी विश्वविद्यालयों की मीटिंगों की अध्यक्षता पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बुधवार की मीटिंग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में विशेष महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि न्यायालय ने मुख्यमंत्री को अब यह अधिकार विधिवत रूप से दे दिया है।

मीटिंग के एजेंडा का एक मुख्य बिंदु अनुदान की माँग भी है। इस पर बाद में और चर्चा होगी तथा 24 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी जायेगी।

इस मीटिंग का फोकस उन वाइस चान्सलरों पर रहेगा, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल आर.एन. रवि ने की थी, तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे सरकार के निर्देशों के अनुरुप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन या सुझावों की किसी प्रकार की अवज्ञा या उपेक्षा स्वीकार्य नहीं होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्यपाल ने नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की जोरदार वकालत की थी, जबकि राज्य सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने इसे व्यापक, क्रान्तिकारी तथा रुपान्तरण करने वाली नीति बताया है। अब राज्य सरकार ने स्टेट एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने के लिये एक कमेटी गठित कर दी है।

मेहुल चोकसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भतीजे नीरव मोदी पर पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

तेलंगाना में अनुसूचित जाति का वर्गीकरण लागू

तेलंगाना देश का पहला राज्य, जहाँ यह व्यवस्था लागू हुई है

- **सरकारी आदेश के अनुसार, इस संबंध में विधानमंडल के अधिनियम को 8 अप्रैल को राज्यपाल ने मंजूरी दी तथा 14 अप्रैल को इसे गजट में प्रकाशित किया गया।**

हैदराबाद, 14 अप्रैल। तेलंगाना ने सोमवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके साथ ही तेलंगाना आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात की जानकारी दी।

तेलंगाना सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर रिटायर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों I, II और III में विभाजित किया जाना चाहिए।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि, तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, समूह-1 में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिणक रूप से वंचित 15 अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि समूह-3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप-समिति के अध्यक्ष मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दी गई। उन्होंने कहा कि, राज्य में एससी वर्गीकरण लागू किया जाएगा। इस संबंध में एक जीओ जारी कर उसकी पहली प्रति सीएम रेवंत रेड्डी को सौंपी गई है।

मंत्री रेड्डी ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है। मंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में पिछली सरकारों ने वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने तक ही खुद को सीमित रखा और कभी आगे नहीं बढ़ ाया। उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार में अब सभी नौकरी रिक्तियों को एससी के लिए उप-वर्गीकरण के अनुसार भरा जाएगा।

चीन ने अमेरिका पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चूंकि ऐसे लाइसैंस जारी करने का तंत्र अभी सक्रिय नहीं हुआ है, इससे उद्योग जगत चिंतित है कि यह प्रक्रिया लम्बी खिंच सकती है और चीन के बाहर इन खनिजों की कमी हो सकती है। यह कदम, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि सभी देशों को हो रहे निर्यात को प्रभावित करता है।

यह कदम दर्शाता है कि चीन आवश्यक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में अपनी मजबूत पकड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है।

हालांकि, यह निर्यात नियंत्रण पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं है, लेकिन बीजिंग निर्यात लाइसैंस की संख्या सीमित कर आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां चीन के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग करती हैं।

हालांकि, अमेरिका के पास कुछ रेयर अर्थ तत्वों का भंडार है, लेकिन वे इतने नहीं है कि वह अपने रक्षा ठेकेदारों को इनकी पर्याप्त आपूर्ति कर सके।

बीजिंग पहले ही तीन धातुओं के अमेरिका को निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है और कई अन्य पर निर्यात नियंत्रण लागू कर चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर प्रतिबंध खास महत्व रखता है, क्योंकि इन पर चीन ने नियंत्रण और कड़ा कर लिया है।

चीन द्वारा जिन भारी रेयर अर्थ धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई गई है, उनका उपयोग चुंबक बनाने में होता है- जो कि इलैक्ट्रक कारों, ड्रोन, रोबोट, मिसाइलों, स्पेसक्राफ्ट और पेट्रोल चालित वाहनों के लिए आवश्यक इलैक्ट्रक मोटर्स के निर्माण में अनिवार्य हैं।

इन धातुओं की जरुरत जेट इंजन, लेज़र, कार हेडलाइट्स और कुछ विशेष स्पार्क प्लग्स व कैपेसिटर्स के निर्माण में भी होती है- जो कि एआई सर्वरों और स्मार्टफोनों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर चिप्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908